न होकर एक बिकाऊ माल है।

इसके बाद अगला कदम है शिक्षा क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश की परिस्थितियां तैयार करना। यह काम भी चालू है। संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर सरकारी सहायताओं की राशि लगातार कम की जा रही है और खुद संसाधन जुटाने के फार्मूले के तहत प्रवेश से लेकर अन्त तक अध्ययन की विभिन्न सुविधाओं के लिए छात्रों से मोटी रकमें वसूल की जा रही हैं। स्थिति ऐसी सीमा तक पहुंचा देने का लक्ष्य है जब शिक्षकों-कर्मचारियों की तनख्वाहों तक के लिए सरकार अपने हाथ उठा दे। यानी, विश्वविद्यालय बीमार घोषित कर दिये जायें। तब उनके उद्धार के लिए देशी-विदेशी पूंजी के लिए मैदान पूरी तरह खाली हो जायेगा। वैसे, विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालय बीमारी की हालत में आ भी चुके हैं। शिक्षकों-कर्मचारियों को कई-कई माह का वेतन नहीं मिल पा रहा है। नयी भर्तियां लगभग बन्द हैं। शिक्षकों की कमी की भरपाई के लिए शिक्षकों को ठेके पर पढ़ाने का काम दिया जा रहा है।

लेकिन, उच्च शिक्षा क्षेत्र में देशी-विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश में सबसे बड़ी बाधा विश्वविद्यालयों की "राजनीति" है। शिक्षक-कर्मचारी राजनीति चाहे जितनी नखदन्तविहीन हो चुकी हो, जब उनके आर्थिक हितों पर चोट पहुंचेगी, नौकरी पर बन आयेगी तो विरोध की आवाज उठनी स्वाभाविक है। महज फीसें बढ़ाने और सीटें घटाने के सवाल पर ही नहीं, इतिहास गवाह है कि व्यापक सामाजिक मुद्दों पर छात्रों-युवाओं के आन्दोलन सत्ता के लिए जबर्दस्त चुनौती बनते रहे हैं। बिड़ला-अम्बानी की बिरादरी इसीलिए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक पूंजी निवेश के लिए तब तक तैयार नहीं है जब तक कि परिसरों से राजनीति की हर सम्भावना को खत्म न कर दिया जाये। इसीलिए कानून बनाकर परिसरों की राजनीति पर रोक लगाने की सिफारिश की गयी है। विश्वविद्यालयों की रेटिंग करते समय रेटिंग कम्पनियां आर्थिक ब्यौरे के साथ-साथ इस मानक का खास ख्याल रखेंगी कि उस परिसर से "राजनीति" का कितना सफाया हुआ है।

प्रधानमंत्री कार्यालय अपने चहेते 'विशेषज्ञों' की भावनाओं और जरूरतों का विशेष ख्याल रख रहा है। अगले शैक्षणिक सत्र में प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रत्यक्ष निर्देशन में उच्च शिक्षा में "सुधार" की योजना फैसलाकुन मुकाम पर पहुंचाने का 'मास्टर प्लान' तैयार हो रहा है।

क्या शिक्षक-कर्मचारी और छात्र राजनीति इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है? ●

मथुरा में फीसवृद्धि के खिलाफ छात्राओं का आन्दोलन

एक स्वतःस्फूर्त विस्फोट जो भविष्य की आहट दे गया

आगरा मंडल के शिक्षाजगत में यह एक किस्म का भूचाल था जो कालेज छात्रों की फीस वृद्धि का मसला लिये उठ खड़ा हुआ था। महीना था नवम्बर-दिसम्बर का। न कोई राजनीतिक-सांगठनिक प्रश्रय, न ही योजनाबद्ध मोर्चेबन्दी, मथुरा की छात्राएं स्वतःस्फूर्त सड़कों पर निकल पड़ीं। लक्ष्य था उत्तर प्रदेश सरकार की लुटेरी शिक्षा नीति की मुखालफत। सरकार ने बीच सत्र में कालेजों के लाखों-लाख छात्रों पर अचानक शोषण का जाल फेंका था। सरकार के उस मनमाने फैसले से सीधे तौर पर अभिभावकों की जेब पर डाका डाला गया था। छात्राओं के दिमाग में यही बात कौंध गयी कि उनके संरक्षकों को लूटने के लिए सरकार का कदम निजी स्कूल प्रबन्धकों से भी ज्यादा घटिया और खतरनाक है। क्योंकि यदि राज्य अपने इस प्रयोग में कामयाब हो गया तो उनके लिए आगे की पढ़ाई-लिखाई मानो चने चबाने जैसी कर दी जायेगी।

उधर सरकार का फरमान जारी हुआ और इधर मथुरा शहर के कन्या महाविद्यालयों की छात्राएं मुट्ठी बांधकर सड़कों पर निकल पड़ी। यह ललकार कालेज प्रबन्धन के लिए कम, जिला प्रशासन की नजर में ज्यादा हैरतअंगेज और चुनौतीपूर्ण थी। आन्दोलन उठने पर दो-चार दिनों तक प्रशासन असमंजस की स्थिति में रहा। इसीलिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बीच उस रणनीति पर मतैक्य नहीं रहा कि आन्दोलन का आखिर सामना कैसे किया जाये। नतीजा पुलिस और प्रशासनिक अमले अलग-अलग दमन के स्फुट प्रयोग करने लगे। उससे छात्राओं को अपनी लड़ाई आगे ले जाने में थोड़ी आसानी भी हुई। उस दिन तो छात्राओं की संघर्ष-चेतना ने पूरे आगरा मंडल को ही झकझोर दिया जब मथुरा का होलीगेट अभूतपूर्व चक्का जाम और मानवश्रृंखला की गिरफ्त में आ गया। पूरे शहर की यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त हो उठी। लड़ाकू छात्राओं की मानव श्रृंखला और समाज में अभिभावकों, आम नागरिकों की भी साझेदारी जुड़ गई। पुलिस टुकड़ियां अपने अधिकारियों के साथ मौके पर जमी रहीं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि कोई सबल हस्तक्षेप करतीं। पुलिस अधिकारी मूकदर्शक बने रहे, छात्राओं की ललकार राज्य सरकार की बददिमागी पर बरसती रही। आनन-फानन में ही चौराहे पर सार्वजनिक मंच बना कर सभा की गई। विरोध प्रदर्शन अपने मकसद में पूरी हिम्मत से कामयाब रहा। प्रशासन हाथ मल कर रह गया। ऐसा मथुरा के इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ था कि इतने बहादुराना अंदाज में महिलाओं ने शासन-प्रशासन के मुंह पर तमाचा मारा हो।

मथुरा प्रशासन व प्रदेश सरकार के लिए यह आंदोलन इन अर्थों में भी अपना अलग सरोकार रखता था कि इस जिले से मंत्रिमंडल में चार मंत्री हैं जिनमें श्याम सुंदर शर्मा, सरदार सिंह, दो कैबिनेट स्तर के हैं। इस स्वतः स्फूर्त आंदोलन की मुखरता इन मंत्रियों की स्थानीय राजनीति में सीधे-सीधे खलल पैदा कर रही थी, सो इन चारों के कान अलग से खड़े हुए। पहले तो लखनऊ में गुपचुप कानाफूसियां चलती रहीं। मथुरा प्रशासन से पलपल के हालात की फोन पर सूचना ली जाती रहीं, लेकिन जब एक दिन छात्राओं ने आन्दोलन का रुख मोड़ते हुए होमगार्ड मंत्री श्यामसुन्दर शर्मा के स्थानीय आवास पर ही धावा बोल दिया, उनकी जिला पंचायत अध्यक्ष पत्नी को घर में कैद कर लिया तो प्रशासन की घिग्घी बंध गयी। हुआ यह कि इससे एक दिन पहले प्रशासन ने थोड़ी हिम्मत जुटा कर छात्राओं के साथ कड़ाई कर दी थी। दो-तीन छात्राओं को पीटा-घसीटा गया था। छात्राएं काफी उत्तेजित थीं। लड़ाई हिंसक हो उठी थी। उसी की प्रतिक्रिया था आंदोलन का नया चरण। छात्राओं ने मंत्री के घर में उनकी पत्नी को लखनऊ फोन मिलाने के लिए विवश कर दिया। फोन पर होमगार्ड मंत्री की छात्राओं से सीधे वार्ता हुई। धूर्ततापूर्वक उन्हें खोखला आश्वासन देकर मंत्री ने अपनी और अपने घर वालों की जान छुड़ाई। अब आंदोलन से मथुरा की कानून व्यवस्था का प्रश्न उठ खड़ा होने लगा था। लखनऊ में बैठे चारों मंत्री अपने गृहक्षेत्र में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे।

■ कविताएं

भगतसिंह और अवतार सिंह 'पाश' के शहादत दिवस (23 मार्च) के अवसर पर

मैं पूछता हूं भगतसिंह

पश्चाताप का एक फूल
'इंकलाब जिन्दाबाद' के घोष को
अनारकली की तरह चिनकर
राजभवन की दीवारों में
हम रमेंगे फिर
गोरी सत्ता की प्रशस्ति में
किसने सोचा था यह ।
किसने सोचा था कि
पचास वर्ष की आजादी के बाद भी
शोषण जारी रहेगा
बस काले-गोरे का भेद नहीं होगा
पूंजीवादी भेड़ियों में ।
नहीं सोचा था तुमने
या तुम्हारे साथियों ने
कि यह देश
जिसकी खातिर तुम जिये पलपल
क्षण-अनुक्षण
निकलेगा इतना कृतघ्न
कि तुम्हारी याद तक न आयेगी ।
मैं पूछता हूं भगतसिंह
तुम क्यों मरे इसके लिए
और क्यों लिया था तुमने
इस देश में जन्म ?

– वेदप्रकाश 'वटुक'

पाश

मिट्टी की महक
बारिश होने से ही फैलती है
वृक्षों की चहक
पत्तियों के वसंत गान से निकलती है
कवि की उमंग
समय की मांग से गूंजती है
पंजाब के ईमान से पाश पैदा होता है
जो विप्लव गायन बनकर
विमुक्ति गीत गाता है।
मिट्टी की महक
पक्षी की चहक
नदी सी चमक
पाश की दमक है
जिसे पंजाब ने अपनाया है
और सारे काव्य संसार ने गले लगाया है
भगतसिंह को देखते-याद करते
स्वयं कविता बन गये।
अराजकता के माहौल में
कवि बनकर क्रान्ति को प्यारे हो गये
पाश के हत्यारे जीते जी लाश हो गये
और पाश मरकर भी
अक्षरों में जी गये
इतिहास रच गये।

– ज्वालामुखी
(प्रख्यात तेलुगु कवि)

मथुरा की छात्राओं के बहादुराना संघर्ष में कदम से कदम मिलाते हुए फिरोजाबाद, आगरा, एटा, अलीगढ़ और हाथरस के छात्र-छात्राओं ने भी साथ दिया। फीस वृद्धि विरोधी मोर्चेबंदी की, रास्ते जाम किये, गिरफ्तारियां हुईं, ट्रेनों का आवागमन ठप रहा और दूसरी ओर से दमन का सिलसिला जारी रहा। इसी बीच एक अन्य मंत्री को अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर मथुरा के सर्किट हाउस में चोर दरवाजे से भागना पड़ा। प्रेस कान्फ्रेन्स तक करने की हिम्मत नहीं हुई। इससे छात्राओं के अभिभावकों में भी नाराजगी फैली। आंदोलन चल ही रहा था कि मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह भी दो बार मथुरा आकर अपनी फजीहत करा गये। वृंदावन और कोसीकलां की जन सभाओं में बीच भीड़ से बैनर व काले झंडे दिखाते हुए छात्राओं ने उन्हें ललकारा। वृंदावन की सभा में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि लखनऊ जाकर वह शीघ्र ही समस्या का समाधान छात्र दरबार में घोषित करेंगे। तभी उन्हें पुनः मथुरा आना पड़ा। कोई निर्णय सरकार नहीं ले सकी थी, नतीजा हुआ कि कोसीकलां की सभा में छात्राओं ने और पुरजोर ढंग से विरोध जताया। पूरे घटनाक्रम से आजिज पुलिस ने सभा खत्म होने पर मुख्यमंत्री के रवाना होते ही सरकारी इशारों पर छात्राओं को घसीट-घसीट कर पीटा और जीपों में ठूंसकर थाने पर ले गई। इस घटना से एक बार फिर पूरे आगरा में गुस्से की लहर फैल गई। विरोध प्रदर्शनों ने जोर पकड़ लिया। मथुरा में सैकड़ों छात्राओं को कोतवाली परिसर में सारी रात खुले आसमान के नीचे रखा गया और उनके अभिभावकों से मिलने-जुलने तक नहीं दिया गया। प्रशासन की शर्त थी कि छात्राएं मुचलके भर कर जमानत ले लें, पर वे उस पर कतई राजी नहीं हुईं। आखिरकार हार कर अगले दिन बगैर शर्त सभी छात्राओं को छोड़ने के लिए प्रशासन मजबूर हुआ।

सरकार छात्राओं की फीस वृद्धि के मसले पर आज तक धूर्ततापूर्ण चुप्पी साधे हुए है राज्य के मुखिया और मथुरा से निर्वाचित तीनों मंत्रियों के विरोधाभासी बयान बताते हैं कि दोनों ही का इरादा एक है, फीसवृद्धि वापस न लेना। उधर आंदोलनरत छात्राओं का मनोबल तोड़ने की चालें भी कालेज प्रबन्धन स्तर पर चली जा रही हैं। छात्राओं का पठन-पाठन अस्तव्यस्त हो चला है और परीक्षाएं सिर पर हैं।

इस समूचे आंदोलन के साथ मुख्य दिक्कत रही दृष्टिकोण और सांगठनिक योजनाबद्धता का अभाव। सरकार के इशारे पर प्रशासन जिस तरह चौकन्ना हो उठा था, उससे जूझने और राज्य की समूची शिक्षा नीति की बखिया उधेड़ने के लिए जैसी इच्छाशक्ति आंदोलन की रगों में होनी चाहिए थी, वह थी तो लेकिन इसे कोई समझदारी से संचालित करने वाला नहीं था, जिससे एक अच्छे खासे आंदोलन को दिशाहीनता और बीच रास्ते की थकान से नहीं बचाया जा सका। बहरहाल, आंदोलन इतना संदेश तो दे ही गया कि सरकार जनता को जितनी आसानी से किनारे लगा कर अपनी खतरनाक नीतियों को थोपना चाहती है, हालात अब उतने आसान रहे नहीं। भीतर ही भीतर ईंट का जवाब पत्थर से देने की चिंगारी खूब सुलगती जा रही है। समय आने पर वह लपटों का आकार ले सकती है जो समस्त तंत्र को झुलसा कर राख कर देगी।

● बीना, वन्दना, रंजना